# जापान-उत्तर कोरिया घनिष्ठता: क्या इससे संबंध सामान्य होंगे?

*डॉ. शमशाद ए. खान **

उत्तर कोरिया के साथ जापान के संबंधों में अप्रत्याशित गर्मजोशी देखी जा रही है। उत्तर कोरिया एक अलग-थलग पूर्वी एशियाई देश है जिसके साथ टोक्यो के औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। उत्तर कोरिया द्वारा स्पष्टत: अपनी आसूचना एजेंसियों को भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए, 1970 और 1980 के दशकों में जापानी नागरिकों का अपहरण किया जाना टोक्यो और प्योंगयांग के बीच के विवादास्पद मुद्दों में से एक रहा था; इस प्रकार यह कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने में एक प्रमुख बाधा था। तथापि, दोनों ही देश इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होते हैं और इन्होंने बातचीत को फिर से प्रारंभ कर दिया है जो वर्ष 2008 से ही रूका हुआ था। जापानी मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यदि दोनों पक्ष आपसी संपर्क बनाए रखें और अपहरण के मामले को सुलझा लें तो इससे इन दोनों पड़ोसियों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

जापानी नागरिकों के अपहरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए, जापान और उत्तर कोरिया के शीर्ष राजनयिकों ने पिछले तीन महीनों के दौरान स्टॉकहोम और बीजिंग में अनेक वार्ताएं की हैं। जिसे एक प्रमुख सफलता माना जा सकता है, उसके अनुसार, जुलाई के प्रारंभ में, उत्तर कोरिया अगवा किए गए जापानियों की नियति के संबंध में जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन करने पर सहमत हो गया। इसके बदले में, जापान ने उत्तर कोरिया पर वर्ष 2006 में लगाए गए प्रतिबंधों में से कुछ को हटा लिया जो जापान ने उस समय उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु और मिसाइल परीक्षण किए जाने के बाद लगाए थे। उनके आपसी तालमेल के भाग के रूप में, जिसे 'कार्रवाई के बदले कार्रवाई' सिद्धांत कहा जाता है, जापान ने निम्नलिखित

प्रतिबंधों को एकपक्षीय रूप से हटा लिया है :-

1. जापान की यात्रा करने वाले उत्तर कोरियाई लोगों पर यात्रा प्रतिबंध।
2. उत्तर कोरिया को 3 मिलियन येन से अधिक धनराशि का प्रेषण करने और 100,000 येन से अधिक मूल्य की नकद राशि उस देश में ले जाने पर प्रतिबंध, दोनों कार्यों के लिए सरकार को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
3. मानवीय प्रयोजनों के लिए उत्तर कोरियाई पंजीकृत नौकाओं/जलयानों का जापानी पत्तनों में प्रवेश पर रोक।

विशेष रूप से, उत्तर कोरिया पर उपर्युक्त प्रतिबंध सिंज़ो अबे सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल के दौरान लगाए गए थे। ये प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त लगाए गए थे। अपने विगत रूख से विपरीत, अबे ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अपहरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बताया है, कुछ हद तक इसलिए कि अपहृत लोगों के परिवारवाले बुढ़े होते जा रहे हैं।

पिछले दिनों, अबे सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपहृतों के परिवारों की ओर से दबाव का सामना कर चुकी है जब उन्होंने अनेक विरोध प्रदर्शन आरंभ किए और अपने अभ्यावेदन सरकार को सौंपे। चूंकि यह मुद्दा मानवीय प्रकृति का है, इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने, जो जापान द्वारा एकतरफा प्रतिबंधों को उठा लेने के विरूद्ध थे, जापान द्वारा की गई पहल पर मौन प्रतिक्रिया दी। सिओल/सउल ने कहा कि वह आशा करता है "वार्ता दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच निकट संप्रेषणों के आधार पर की जाएगी।" अमेरिका ने जापान से इस अपहरण मुद्दे को एक "पारदर्शी तरीके" से सुलझाने की उम्मीद जताई। तथापि, वे महसूस करते हैं कि जापान की कार्रवाई उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को निरर्थक बना देगा और उस अड़ियल शासन को अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए राजी करना कठिन हो जाएगा।

यद्यपि जापान में अधिकारीगण इस जापानी प्रस्ताव को विशुद्ध मानवीय कदम बताते हैं, तथापि, आलोचकों का मानना है कि टोकियो और प्योंगयांग के बीच दूर हुआ यह गतिरोध केवल मानवीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहेगा; बल्कि, यह राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। नि:संदेह, जापान और उत्तर कोरिया दोनों के एक-दूसरे के साथ आने के अपने-अपने कारण हैं। उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण

करने जैसे अपने आक्रामक व्यवहार के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग रहता है। इसके अतिरिक्त, इसने किम जोंग-यून शासन में नम्बर दो के राजनीतिक चेहरे जॉंग सोन-तेक को फांसी देने के कारण अपने सबसे मूल्यवान सहयोगी चीन को नाराज कर दिया। किम जोंग-यून के प्रशासन संभालने के बाद से चीन ने कभी भी उत्तर कोरिया के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता नहीं की है और इस प्रकार उत्तर कोरिया स्वयं को और भी अलग-थलग महसूस करता है। इसी प्रकार, जापान भी ऐतिहासिक मुद्दों पर मतभेदों और प्रादेशिक विवादों के कारण चीन और दक्षिण कोरिया से राजनीतिक अलगाव का सामना करता है क्योंकि उन्होंने जापानी नेतृत्व के साथ राजनैतिक बातचीत पर रोक लगा दी है। टोकियो तथा प्योंगयांग के बीच की यह मैत्री/घनिष्ठता जापानी घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों में यह संदेश दे सकती है कि अब यह इस क्षेत्र में अलग-थलग नहीं रह गया है। इस प्रकार, यह कदम जापान में जापानी प्रधानमंत्री की उस लोकप्रियता को बढ़ाने में मददगार होगा जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मंत्रिमंडल द्वारा कुछ विवादास्पद निर्णयों के कारण तेजी से कम होती जा रही है। जहां तक उत्तर कोरिया का संबंध है, इस कदम से इस अछूत राष्ट्र को कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा क्योंकि यह अपनी अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को बेताब है। यह घनिष्ठता जापान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की उत्तर कोरिया की इच्छा को भी पूरा कर सकती है।

जापान में ही, विश्लेषकों के एक वर्ग को यह संदेह है कि जांच फिर से प्रारंभ करने के कुछ ठोस परिणाम निकलेंगे। उत्तर कोरिया ने विगत में इसी प्रकार के पड़ताल के वायदे किए थे लेकिन अब तक इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। जापानी सरकार ने 17 नागरिकों की एक सूची प्रस्तुत की थी जिनके बारे में माना जाता था कि उत्तर कोरिया द्वारा 1970 की दशक के प्रारंभिक वर्षों में और 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में उनका अपहरण कर लिया गया था। तथापि, जापानी गैर-सरकारी संगठनों के अनुमान सुझाते हैं कि लगभग 470 लोगों का अपहरण इस एकांतवासी राष्ट्र की जासूसी एजेंसियों द्वारा किया गया था। वर्ष 2002 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जूनीचीरो कोइजूमी को अपनी अचानक प्योंगयांग यात्रा के बाद उत्तर (कोरिया) से पांच अपहृत व्यक्तियों को वापस लाने में सफलता मिली थी। कोइजूमी से अपनी मुलाकात के दौरान, उत्तर कोरिया के तत्कालीन नेता किम जोंग II ने जापानी नागरिकों/राष्ट्रिकों के अपहरण की बात स्वीकार की। उन्होंने भी एक पड़ताल प्रारंभ की और बाद में जापान को सूचित किया कि आठ अपहृत व्यक्तियों की मौत हो गई थी और शेष चार ने कभी उत्तर कोरिया में प्रवेश ही नहीं किया था। इस दावे को जापान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसने नए सिरे से जांच की मांग की। अपहरण के मुद्दे पर बातचीत को जापान द्वारा कई बार रोक दिया गया था विशेष रूप से तब जब उत्तर (कोरिया) ने उग्र कदम उठाए और मिसाइल परीक्षण किए।

उत्तर (कोरिया) ने जापान-उत्तर कोरिया वार्ताओं के बीच में ही और चीनी राष्ट्रपति के दक्षिण कोरिया दौरे के ठीक बाद इस वर्ष 27 व 29 जून को छोटी दूरी के मिसाइल परीक्षण किए। जापान ने इस उग्र कदम पर उत्तर कोरिया के समक्ष अपना विरोध अवश्य जताया परन्तु पूर्ववर्ती अवसरों से विपरित इसने वार्ताओं को स्थगित नहीं किया। यह कार्रवाई इस तथ्य को दर्शाता है कि जापान की नजर कुछ दीर्घकालिक लाभों पर है और यह उत्तर (कोरिया) से संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन रिपोर्टों के बीच कि अनेक अपहृत लोग अभी भी जीवित हैं, जापानी मीडिया में ये अटकलें हैं कि प्रधान मंत्री सिंज़ो अबे जापानी अपहृत व्यक्तियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर कोरिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं। जापानी विदेश मंत्री फ्यूमियो किशिदा ने जापानी संसद/सम्मेलन में कहा है कि अबे की उत्तर कोरिया का दौरा अपहरण मामले को हल करने का एक तरीका हो सकता है।

यदि अबे वास्तव में प्योंगयांग की यात्रा करते हैं और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता से वार्ता करते हैं तो यह जापान-उत्तर कोरिया के बीच एक नए अध्याय की शुरूआत का प्रतीक होगी। उत्तर कोरिया की ओर अबे की इस चाल पर करीबी नजर यह संकेत देती है कि वे उत्तर कोरिया के समक्ष दो-तरफा रणनीति अपना रहे हैं। एक ओर, वे उत्तर (कोरिया) द्वारा पेश की जा रही सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से त्रिपक्षीय समन्वय जारी रखना चाहते हैं जबकि दूसरी ओर, वे उत्तर (कोरिया) के आक्रमक व्यवहार को उदार/संयत बनाने में स्पष्ट रूप से उससे संपर्क करके कुछ अलग अपरंपरागत कदम उठाना चाहते हैं। दक्षिण कोरियाई सूत्र संकेत दे रहे थे कि उत्तर कोरिया चौथे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। तथापि, उत्तर कोरिया ने अभी तक यह परीक्षण नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया के प्रति जापान के हाल के संधि प्रस्ताव ने प्योंगयांग को परीक्षण स्थगित करने पर बाध्य कर दिया है। यह (प्योंगयांग) अच्छी तरह जानता है कि यदि यह आगे परीक्षण करता है तो जापान अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेगा और यह कदम किम जोंग-यून शासन व्यवस्था को और भी अलग-थलग कर देगा।

आलोचकों ने जापान पर उत्तर कोरिया पर से प्रतिबंध उठा लेने का दोषारोपण किया है क्योंकि उनका मानना है कि जापान का यह कदम प्योंगयांग के प्रक्षेपास्त्र और परमाणु कार्यक्रम पर लगाम कसने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को कमजोर करेगा। तथापि, इन दोनों (देशों) के बीच की इस प्रारंभिक सौजन्यता/मिलनसारिता को विशुद्ध नकारात्मक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। म्यांमार इस क्षेत्र में

नवीनतम सुपरीक्षित मामला है; अमेरिका-म्यांमार वार्ता ने नायी पेई ताठ का दृष्टिकोण बदल दिया और इसे विश्व के संपर्क में रहने के लाभों का अहसास हुआ और इस कदम ने उस देश में राजनीतिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार, अपहरण मामले को सुलझाने के लिए जापान और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आ सकता है, जिससे प्रतिबंधों में और ढ़ील तथा उत्तर कोरिया को जापानी आर्थिक सहायता मिल सकती है। प्योंगयांग का किम जोंग-युन शासन भी आर्थिक रूप से जीवंत पड़ोसी के साथ संपर्क रखने के लाभ देख सकता है और इससे इसे वैसे कदम न उठाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है जिनके कारण यह अलग-थलग पड़ा हुआ है। चूंकि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को थोपने और उसका बहिष्कार करने के कठोर उपायों के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले, इसलिए नरम रवैया अपनाने की वैकल्पिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे कदम उठाने के लिए जापान की प्रशंसा की जानी चाहिए; तथापि, इसे (जापान को) सावधानीपूर्वक निगाह रखनी चाहिए कि क्या (उत्तर कोरिया से) उसका संपर्क उत्तर कोरिया के आक्रामक व्यवहार को शांत करने में सहायक है या इससे उसका हौसला और बढ़ रहा है।

** डॉ. शमशाद ए. खान भारतीय विश्व कार्य परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*